उद्योगों के लिए 20 हजार एकड़ से अधिक लैंड बैंक है तैयार

यूपीसीडा के एमडी महेश माहेश्वरी से विशेष बातचीत

अमर उजाला ब्यूरो

कानपुर। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यू पी सी डा) औद्योगिक क्षेत्रों और उद्यमियों की सुरक्षा और आ धु नि क सुविधाएं मुहैया कराने के लिए काम कर रहा है। यूपीसीडा के पास 20 हजार एकड़ का लैंड बैंक तैयार है।

सभी कार्य प्रदेश सरकार की सेफ सिटी परियोजना के तहत कराए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने 292 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है। यूपीसीडा के अनुसार ये जमीनें प्रदेश के अलग-अलग जिलों में हैं। रायबरेली में 70 एकड़, प्रतापगढ़ में आटो ट्रैक्टर इंडस्ट्री की 97 एकड़, बाराबंकी में 70, भारत पंप एंड कंप्रेशर लिमिटेड की नैनी प्रयागराज में स्थिति 231 एकड़ जमीन के अलावा लखनऊ में करीब 100 एकड़ भूमि संकलित कर ली गई है। औद्योगिक क्षेत्रों की निगरानी के लिए इन क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से लैस सीसीटीवी कैमरे लगाएं जाएंगे। यह कैमरे सीधे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जुड़े होंगे। अमर उजाला ने यूपीसीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मयूर माहेश्वरी से बातचीत की। पेश है प्रमुख अंश...

■ सेफ सिटी परियोजना के तहत क्या-क्या किया जाना है ?

इस परियोजना के तहत औद्योगिक क्षेत्र में महिलाओं, उद्यमियों, कर्मचारियों, श्रमिकों की सुरक्षा का बेहतर प्रबंधन होगा। औद्योगिक क्षेत्रों में 55 करोड़ रुपये से 25 हजार स्ट्रीट लाइटें और 25 करोड़ से 480 हाई मास्ट लाइटें लगाने का काम हो रहा है। 43 पुलिस चौकी भी बनाई जा रही है। महिलाओं के लिए हॉस्टल व कैंटीन बनेगी।

■ उद्यमियों और वहां पर काम करने वाले कामगारों के लिए क्या सुविधाएं दी जा जाएंगी?

गौतमबुद्ध नगर के सूरजपुर, बरेली, वाराणसी, लखनऊ आदि औद्योगिक क्षेत्रों में क्रेच (पालना गृह) बनाए जा रहे हैं, ताकि महिला श्रमिकों के बच्चों की बेहतर देखभाल हो सके। औद्योगिक क्षेत्रों में हेल्थ एटीएम लगाया रहा है।

■ बुंदेलखंड के विकास के लिए प्राधिकरण की क्या पहल है?

बुंदेलखंड के विकास के लिए नया प्राधिकरण तैयार किया गया है। करीब 20 हजार एकड़ जमीन खरीदने की प्रक्रिया है। ये सारी जमीनें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और झांसी हाईवे के आसपास होंगी। एक वर्ष में जमीन अधिग्रहण का कार्य पूरा हो जाएगा।

■ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत प्राधिकरण की ओर से क्या किया जा रहा है?

मानचित्र पास करने, भूखंड आवंटन की प्रक्रिया समेत 33 सेवाएं ऑनलाइन की जा चुकी हैं। समयबद्ध ढंग से आवेदनों का निस्तारण हो रहा है। अब तक करीब 15 हजार आवंटी इस योजना का लाभ भी ले चुके हैं।

■ नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की दिशा में क्या कदम उठा रहे हैं ?

एक लाख करोड़ के अनुबंध किए हैं। संडीला में 10 हजार करोड़ का निवेश औद्योगिक इकाइयों के रूप में आ चुका हैं। कानपुर के रमईपुर में मेगा लेदर क्लस्टर के लिए 150 एकड़ भूमि अतिरिक्त ली जा रही है। बरेली के बहेड़ी, आगरा आदि जगहों पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जा रहे हैं। औरैया के प्लास्टिक पार्क के लिए गेल से कच्चा माल मिलेगा। ललितपुर में फार्मा पार्क के लिए लगभग 1500 एकड़ जमीन का आवंटन सरकार ने यूपीसीडा के पक्ष में कर दिया है।